राकांपा से छुपी युति को सीएम का 'राम-राम'

अब राकांपा पर 'हल्लाबोल' की तैयारी

प्रतिनिधि, 13 दिसंबर

नागपुर- शिवसेना को कब्जे में रखने के लिए समय-समय पर राकांपा को नजदीक करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस अब अपनी नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं. राष्ट्रवादी कांग्रेस ने हल्लाबोल मोर्चा निकालते हुए कर्जमाफी के मसले पर सीधे मुख्यमंत्री को निशाना बनाया, ऐसे में अब देवेंद्र फड़णवीस भी सीधे-सीधे राकांपा पर 'हल्लाबोल' करने की तैयारी में हैं.

कांग्रेस-राकांपा आघाड़ी सरकार के दौरान हुई कर्जमाफी के घोटालों की सूची तैयार की गई है, विशेषतः जिला बैंक में हुए घोटाले पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है. इसका कारण यह है कि उस वक्त और आज भी अधिकांश जिला बैंक पर राकांपा का ही वर्चस्व है. वर्धा, सोलापुर, अहमदनगर, बुलढाणा सहित कुछ जिला बैंक के घोटाले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अथवा विधानमंडल में उपलब्ध अन्य मार्ग से इन्हें उजागर करने की नीति पर काम किए जाने के संकेत मिल रहे हैं. साथ ही शक्कर मिल घोटाले, ड्रिप इरिगेशन घोटाले, राज्य सहकारी बैंक के घोटालों को लेकर भी कुछ आला नेताओं पर कार्रवाई की जा सकती है.जानकारों का कहना है कि शिवसेना की ओर से रोजाना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के साथ केंद्र और राज्य सरकार की आलोचना की जाती है, इसी वजह से भाजपा ने शिवसेना को काबू में रखने के लिए राकां को नजदीक रखा था ताकि शिवसेना के सत्ता से बाहर होने पर वह राकांपा के साथ युति कर अपनी सरकार को बचा ले जाएं. इसी वजह से भाजपा नेता बार-बार कहते थे कि शिवसेना सत्ता से बाहर भी हो गई तो सरकार को कोई खतरा नहीं है. राकांपा के अनेक वरिष्ठ नेताओं पर घोटाले के आरोप होने के बावजूद कोई कार्रवाई न होने की वजह से भाजपा के वोटर भी नाराज थे.

लेकिन शिवसेना के रवैये को देखते हुए राकांपा को नाराज न करने की बात कहकर भाजपा नेता अपने वोटरों को समझाते रहते थे. लेकिन अब सूत्रों ने संकेत दिया है कि राकांपा के साथ चल रहा यह 'रोमांस' समाप्त कर उसका मुकाबला 'हेड ऑन' करने का वक्त आ गया है, मुख्यमंत्री समेत भाजपा पर यह आरोप लगता रहा है कि यह राकांपा के साथ नरमी से पेश आ रही है. ऐसे में यह नजदीकी डेढ़ वर्ष बाद होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसे भारी पड़ सकती है.

महानगरपालिका, जिला परिषद तथा नगरपालिका चुनाव में बड़ी सफलता अर्जित कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने राज्य की राजनीति पर अपनी पकड़ पहले ही साबित कर दी है. ऐसे में अब वे अपने ऊपर लगे राकांपा के साथ नजदीकी के ठप्पे को मिटाने की तैयारी में जुट गए हैं.

विद्यार्थी परिषद के चुनाव जून में होंगे

शिक्षा मंत्री तावड़े ने दी जानकारी

प्रतिनिधि, 13 दिसंबर

नागपुर- नए महाराष्ट्र विश्वविद्यालय एक्ट में विद्यार्थी परिषद चुनाव को मंजूरी दी गई है. इसके बावजूद इस वर्ष विद्यार्थी परिषद के चुनाव नहीं लेने के संबंध में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है. कॉमन स्टेच्यूट नहीं होने से ही परिषद के चुनाव में देरी हो रही है. स्टेच्यूट बनाने का कार्य पूरा हो गया है. लेकिन अब परीक्षाओं का सीजन शुरू हो जाएगा, आगामी शैक्षणिक सत्र यानी जून में विद्यार्थी परिषद के चुनाव होंगे. यह जानकारी शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने पत्रकारों से चर्चा में दी. राज्य में दिसंबर 2016 के विधिमंडल सत्र में नया विधि एक्ट लागू किया गया. 1 मार्च से राज्यभर के कृषि विश्वविद्यालयों में नया एक्ट लागू भी हो गया, इसमें विद्यार्थी परिषद चुनाव का भी प्रावधान किया गया है. मंगलवार को राज्य सरकार ने विधानसभा में विश्वविद्यालयों में 2017-18 शैक्षणिक वर्ष के लिए विद्यार्थी परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है. इसके अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर एक और संलग्नित महाविद्यालयों में एक-एक विद्यार्थी परिषद का गठन किया जाएगा. परिषद में विद्यार्थी प्रतिनिधि सहित उपकुलपति, प्र-उपकुलपति, विद्यार्थी विकास संचालक, क्रीड़ा व शारीरिक शिक्षा संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना संचालक सहित अन्य अधिकारियों का समावेश होगा.

पारदर्शी होगी प्रक्रिया

नियुक्त विद्यार्थी प्रतिनिधि विवि की सिनेट, बोर्ड ऑफ स्टडीज और अन्य प्राधिकरणों में रहेंगे. नीति निर्धारण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी. नए एक्ट में विद्यार्थी कल्याण की अनेक योजना प्रस्तावित है. इनमें विद्यार्थी विकास मंडल, विद्यार्थी शिकायत निवारण सेल, क्रीड़ा व शारीरिक शिक्षा मंडल गठित किए जाएंगे. इनमें भी विद्यार्थी प्रतिनिधियों का समावेश रहेगा, लिंगढोह समिति और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद विवि एक्ट में विद्यार्थी संघ चुनाव को जगह दी गई है. अध्यक्ष, सचिव, महिला प्रतिनिधि, आरक्षित वर्ग प्रतिनिधि के चुनाव होंगे.

सीएम से चर्चा कर निकालेंगे मार्ग

नागपुर सहित राज्यभर में शिक्षकों ने अशैक्षणिक काम के विरोध में आंदोलन की शुरुआत की है. अध्यापन के अलावा भी अन्य कार्य दिए जा रहे है, इससे छात्रों का नुकसान हो रहा है. तावड़े ने कहा कि यह सिलसिला आज का नहीं है, बल्कि पिछले 25 वर्षों से जारी है. लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से शिक्षकों का विरोध बढ़ गया है. आंदोलन में शामिल शिक्षक नेता राजकीय हितसंबंध से होने का आरोप लगाया. शिक्षकों को जिप व मनपा द्वारा भी अशैक्षणिक काम सौंपे जाते हैं. शिक्षा विभाग का कार्य अनुदान देने तक सीमित है, शिक्षकों को अशैक्षणिक कामकाज से दूर करने के लिए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस से चर्चा कर रास्ता निकाला जाएगा.

नेता फैला रहे भ्रम

उन्होंने बताया कि राज्य में 10 से कम छात्र संख्या वाली 1317 स्कूलों को बंद किया जाएगा. इन स्कूलों के छात्रों को आसपास की स्कूलों में समावेशित किया जाएगा. अनेक शिक्षक नेता स्कूल बंदी के कारण 2 लाख छात्रों के नुकसान की भ्रामक जानकारी फैलाकर दिशाभूल कर रहे हैं. वास्तव में देखा जाए तो 1317 स्कूलों में छात्र ही कम है, इस वजह से केवल 13,000 छात्रों को ही आसपास की स्कूलों में स्थानांतरित किया जाना है.

खामगांव बनेगा कार्गो हब

चौतरफा केंद्र निर्माण से बनेगा राज्य का मध्यवर्ती केंद्र

संवाददाता, 13 दिसंबर

खामगांव - शहर से गुजरने वाले सड़क निर्माण के काम को गति मिल रही है. फोरलेन के साथ खामगांव में फोरलेन का चौतरफा केंद्र का निर्माण भी होगा. यह काम पूरा होने पर खामगांव राज्य मध्यवर्ती केंद्र बन कर उद्योग एवं यातायात बढ़ेगा. जिसके चलते भविष्य में खामगांव कार्गो हब के रूप में बनेगा. केंद्र एवं राज्य सरकार सड़क निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है. प्रकल्प अंतर्गत भाऊसाहब फुंडकर एवं विधायक अधि. आकाश फुंडकर ने केंद्रीय भूतल मंत्री नितिन गड़करी एवं राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से बार-बार संपर्क कर खामगांव में जानेवाले चारलेन के चौड़ाईकरण के काम की शुरूआत हो चुकी है. यह काम प्रगति पथ पर है. इसका लाभ बड़े पैमाने पर खामगांव शहर को होगा.

यातायात सुविधा मिलने पर बड़े उद्योग शहर में आएंगे तथा खामगांव कार्गो हब बनेगा. नए महामार्ग काम से खामगांव राज्य के मध्यवर्ती जगह पर होगा. नागपुर, मुंबई, इंदौर, पंढरपुर, सूरत, पुणे, औरंगाबाद एवं अन्य बड़े शहरों में जानेवाला यातायात खामगांव से हो कर ही जाएगा, जिसके लिए महामार्ग चौतरफा केंद्र खामगांव में तैयार होगा. यह बात उद्योग एवं यातायात की दृष्टि से सुविधाजनक है. केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी की संकल्पना से 'भारत माला' इस बॉध महामार्ग खामगांव को जोड़ा जाएगा, जिससे खामगांव का विकास होगा.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के ड्रीम प्रोजेक्ट वाले मुंबई-नागपुर समृध्दि महामार्ग खामगांव के समीप लगभग 50 किमी पर जालना मार्ग को जोड़ा जाएगा. मार्ग के लिए भूमि संपादन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस मार्ग का काम होने पर नागपुर एवं मुंबई को जाने के लिए समय कम लगेगा. अन्य राज्य का यातायात खामगांव से होकर जोड़ा जाएगा.

मेट्रोसिटी बनेगा खामगांव

खामगांव निर्वाचन क्षेत्र के सभी महामार्ग को चारलेन किया जाएगा, जिसके चलते उद्योग एवं विकास में वृध्दि होगी. प्रस्तावित कपास संशोधन एवं प्रक्रिया केंद्र के लिए बड़े उद्योग तथा कारखाने खामगांव में खड़े किए जाएंगे. अब खामगांव शहर के कदम मेट्रो सिटी की ओर बढ़ रहे हैं.

-अधि. आकाश फुंडकर
विधायक,खामगांव

ये है जोड़नेवाले मार्ग

अजंता-खामगांव-बैतूल
पंढरपुर-खामगांव-शेगांव
अमरावती -खामगांव-धूलिया
जालना- खामगांव-अकोला
इंदौर-खामगांव
सूरत-खामगांव-नागपुर
मुंबई-नागपुर समृध्दि महामार्ग

सेंधमारी का अब तक सुराग नहीं

स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी फेल

प्रतिनिधि, 13 दिसंबर

नागपुर- मुख्यमंत्री व गृहमंत्री फड़णवीस के निवासस्थान के पीछे हुई एक करोड़ रुपये सेंधमारी को लेकर 36 घंटों से ज्यादा समय हो जाने के बाद भी पुलिस के हाथों अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है. शीतकालीन अधिवेशन के पहला ही दिन पूरा होते-होते चोरों ने सीए व थिंक कन्सल्टन्सी के संचालक पराग परांजपे के घर सेंधमारी कर हीरे और सोने के जेवरातों के साथ की करीब एक करोड़ के माल पर हाथ साफ कर दिया. इस सेंधमारी के बाद पुलिस विभाग में खासी अफरा-तफरी मची. 36घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कोई सुराग हाथ न लगने से स्मार्ट पुलिस के कार्यक्षमता पर भी सवालिया निशान लग गया.

इस दौरान, मंगलवार को परांजपे से संबंधित लोगों की पुलिस ने जांच की. सीताबर्डी पुलिस भी चोरों का सुराग तलाशने में लगी है. स्मार्ट सिटी प्रकल्प के तहत शहर में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं. कई चौराहों पर सीसीटीवी लग भी चुके हैं. लेकिन इन सीसीटीवी में सिर्फ 'लाइव्ह' ही नजर आते है. 'डीव्हीआर मे डाटा सेव्ह' किये जाने की कोई व्यवस्था ही यहां नही दिखती. धरमपेठ में दोपहर के करीब 1.30 पर करीब एक करोड़ की चोरी हो गई, लेकिन सीसीटीव्ही फुटेज से भी किसी तरह की मदद नहीं मिल रही. पुलिस ने परांजपे के घर के पास रहने वालों के भी सीसीटीवी फुटेज की जांच की है. सुरक्षा दीवार वाले दरवाजे की भी सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने अख्तियार में ली है.

मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन का अब तक प्रस्ताव नहीं

सर्वे के लिए स्पेनिश कंपनी एडिफ इलेको की नियुक्ति

प्रतिनिधि, 13 दिसंबर

नागपुर- मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन के लिए अब तक केंद्र सरकार से राज्य सरकार को किसी तरह का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. यह जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में दी है. हालांकि नागपुर-मुंबई बुलेट ट्रेन के लिए रेल मार्ग का अध्ययन करने के लिए रेलवे मंत्रालय ने स्पेनिश कंपनी एडिफ इलेको की नियुक्ति की है. विधान परिषद में शरद रणपिसे, संजय दत्त, धनंजय मुंडे, भाई जगताप सहित कुछ अन्य विधायकों ने इस संदर्भ में सवाल उपस्थित किया था. पूछा गया था कि मुंबई-नागपुर बुलेट ट्रेन प्रकल्प राज्य सरकार के पास विचाराधीन है तो क्या इसके लिए केंद्र सरकार से किसी तरह की विनती की गई है या प्रस्ताव भेजा गया है और यह भी कि केंद्र सरकार से इस संदर्भ में अब तक क्या प्रतिसाद मिला है? इस प्रकल्प के लिए कितना खर्च अपेक्षित है और इसके लिए निधि की व्यवस्था किस तरह की जाएगी? वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की स्थिति क्या है?

वायबल होगा या नहीं

सवाल के जवाब में रावते ने लिखित जवाब में कहा कि इस संदर्भ में आर्थिक व तकनीकी व्यावहारिकता की जांच का काम शुरू है. इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने एडिफ इलेको स्पेनिश कंपनी को फास्ट ट्रैक रेलवे मार्ग का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया है. फिलहाल केंद्र सरकार स्तर पर यह विचाराधीन है और अब तक राज्य सरकार को केंद्र से इस संदर्भ में किसी तरह का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है.

एसटी महामंडल 2,313 करोड़ के घाटे में

5 वर्ष में 15.79 करोड़ यात्री घटे

प्रतिनिधि, 13 दिसंबर

नागपुर- पिछले 5 वर्षों में एसटी महामंडल की बसों में यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में महामंडल का घाटा 2312.72 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया है. यह घाटा वर्ष 2015-16 के अंत तक 1807.23 करोड़ रुपयों का था, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने इस संदर्भ में तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में जानकारी दी है. विधान परिषद सदस्य संजय दत्त, शरद रणपिसे सहित अन्य सदस्यों ने तारांकित प्रश्न का जवाब मांगा था कि क्या एसटी महामंडल में यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आई है और उसके चलते घाटा 2100 करोड़ रुपये से ऊपर चला गया है. सवाल यह भी पूछा गया कि महामंडल की आर्थिक स्थिति सुधारने व महामंडल को हो रहे नुकसान के लिए संबंधित अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई की गई या करने वाले हैं, रावते ने कहा कि नुकसान से उभरने व यात्रियों को आकर्षित करने के लिए विभाग की ओर से अनेक तरह के कदम उठाए जा रहे हैं.

खर्च में कटौती के निर्देश

रावते ने अपने जवाब में कहा है कि एसटी महामंडल की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आय बढ़ाने के साथ ही खर्च में कटौती के निर्देश दिए हैं. यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए हिरकणी सेवा में पुशबैक सीट सुविधा, नई एसी बसें शिवनेरी व शिवशाही की खरीदी, सक्षम मार्ग जांच और अवैध परिवहन पर कार्यवाही, 24 विविध घंटों को 50 से 100 फीसदी यात्रा भाड़ा अनुदान, मासिक-त्रैमासिक पासेस की सुविधा शुरू की गई है. इसके साथ ही ई-टिकट द्वारा रिजर्वेशन, स्मार्ट कार्ड सुविधा शुरू की गई है, इसके साथ ही ई-टिकट द्वारा रिजर्वेशन, स्मार्ट कार्ड सुविधा उपलब्ध कराई गई है. यात्रियों की सुविधा के लिए मोबाइल एप तैयार किया गया है.

1500 बसें भाड़े पर लेंगे

विप सदस्य अनंत गाडगिल के तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में रावते ने कहा है कि अब तक एसटी महामंडल द्वारा 153 शिवशाही एसी बसेस शुरू की गई हैं. 1500 बसों को भाड़ा तत्व पर चलाने की योजना है जिसमें से पहले चरण में 700 बसों के लिए 7 निविदा धारकों का चयन किया गया है. इसके अलावा एसटी महामंडल ने स्वमालकी की 500 बसें लेने का निर्णय लिया है, गाडगिल ने प्रश्न किया था कि एसटी महामंडल ने 2000 एसी बसों की सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक केवल 13 एसी बसें ही शुरू की गई हैं और इससे यात्रियों को असुविधा होने के साथ ही महामंडल को नुकसान हो रहा है.

आज का इतिहास 14 दिसंबर

1799 अमरीका के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन का निधन.
1911 नार्वे का खोजी रोआल्ड एमंड सेन अपने तीन साथियों के साथ दक्षिणी ध्रुव पहुंचने में सफल हुआ.
1918 ब्रिटेन में चुनावों में महिलाओं ने पहली बार मतदान में भाग लिया.
1920 पहली यात्री विमान दुर्घटना लंदन हाऊस पर हुई जिसमें दो चालक और दो यात्री मारे गए.
1931 दो स्कूली छात्राओं शांति दास और सुनीति चौधरी ने कोमिल्ला के कलेक्टर की हत्या रिवाल्वर से कर दी.
1935 चेकोस्लोवाकिया के प्रथम राष्ट्रपति थामस मसारिक ने इस्तीफा दिया.
1947 ब्रिटीश प्रधानमंत्री स्टैनली बाल्डविन का निधन.
1959 आर्क बिशप मकारियोस साइप्रस के प्रथम राष्ट्रपति बने.
1962 मेरीनर द्वितीय अंतरिक्ष यान के शुक्र ग्रह से संदेश भेजना शुरू किया.
1978 राष्ट्रसंघ महासभा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तेल प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया.
1989 सोवियत वैज्ञानिक आंद्रेई सखारोव का निधन.
1991 मशहूर फिल्म निर्देशक सत्यजीत राय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार.
2004 जम्मूतवी एक्सप्रेस फिरोजपुर में एक लोकर ट्रेन से टकरा गई. हादसे में 11 महिलाओं सहित 37 लोगों की मौत.

मूकबधिर परिचय सम्मेलन आज

प्रतिनिधि, 13 दिसंबर

शेगांव- जिला मूक-बधिर एसोसिएशन व क्रीड़ा मंडल खुलढाणा की ओर से 14 दिसंबर को शेगांव में मूकबधिर का राज्यस्तर परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया है. स्थानीय वर्तमान जैन भवन रेलवे स्टेशन के पास यह सम्मेलन आयोजित किया गया है. विकलांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए उक्त उपक्रम लिया जा रहा है.मूकबधिर सम्मेलन से समाज को नई दिशा मिली है. सुबह 9 बजे से नाम पंजीयन फॉर्म दिये जायेंगे. इस सम्मेलन में मूक-बधिर युवक-युवती बड़ी संख्या में शामिल हो, ऐसा आह्वान जिला मूक-बधिर एसोसिएशन की ओर से किया गया है.

अब छात्र बीच में ही बदल सकेंगे विषय

▶▶तकनीकी शिक्षा के लिए डेवलपमेंट प्लान
▶▶सीटों को भरने की कवायद शुरू

प्रतिनिधि, 13 दिसंबर

नागपुर- तकनीकी व उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है. आने वाले वर्षों में उन्हें बीच में ही विषय बदलने की इजाजत मिलेगी. इसके लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग शहर विकास की तरह ही उच्च व तकनीकी शिक्षा का डेवलपमेंट प्लान (डीपी) बनाएगा. तकनीकी व उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों से राज्य सरकार भी चिंतित है. इससे निजात पाने के लिए यह नया तरीका खोजा गया है. हालांकि डेढ़ साल पहले भी इस तरह का प्लान तैयार किया गया था. लेकिन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने इसे नामंजूर कर दिया था. इस बार प्लान मंजूर हो इसके लिए व्यापक अध्ययन के बाद प्रस्ताव बनाया जा रहा है. शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने स्वयं इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि प्लान की अवधि 10 वर्षों की होगी. 10 वर्ष बाद प्लान की समीक्षा की जाएगी. समय के अनुरूप इसमें बदलाव किया जाएगा. तावड़े ने भरोसा दिलाया कि इससे विद्यार्थियों को काफी फायदा होगा. साथ ही उच्च व तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रमों की सीटें खाली नहीं रहेंगी.

विनोद तावड़े

तावड़े ने कहा कि पाठ्यक्रमों की सीटें खाली रहने के पीछे एक मुख्य वजह यह भी है कि विद्यार्थियों की तुलना में उपलब्ध सीटें अधिक हैं. एक कारण यह भी है कि हर साल पाठ्यक्रमों की मांग बदलती रहती है. मांग को देखते हुए विद्यार्थी पाठ्यक्रम में दाखिला लेते हैं. दाखिला लेने के बाद मांग बदल जाती है. विद्यार्थी को रोजगार नहीं मिल पाता. उन्हें यह छूट भी नहीं मिलती कि वे बीच में पाठ्यक्रम के विषय बदल सकें, ताकि मांग के अनुरूप वह शिक्षा हासिल करें.

उन्होंने बताया कि डेढ़ साल पहले इस संबंध में एआईसीटीई को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन खारिज कर दिया गया. इस बार पूरी तैयारी के साथ एआईसीटीई को प्रस्ताव भेजेंगे. एआईसीटीई के अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्त्रबुद्धे ने दावा किया था कि अन्य कॉलेजों को विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं. तावड़े ने इस बयान का खंडन किया.

अकोट, धारणी, चिखलदरा में कर सकेंगे खेती

मेलघाट पुनर्वसितों को मिलेगी ई-क्लास जमीन

संवाददाता, 13 दिसंबर

धारणी- विगत दो दिनों से केलपानी में जमीन के लिए परिजनों के साथ आए कुछ आदिवासी सोमवार की दोपहर के बाद अपने नए गांवों की ओर लौटने लगे, कुछ वहीं रुके हैं, मुख्यमंत्री ने विधायक बच्चू कडू से वार्ता कर 8 गांवों के आदिवासी परिवारों के लिए आवश्यक जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. ज्ञात हो कि शनिवार 9 दिसंबर से मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प से अकोट तहसील में पुनर्वसित हुए 8 गांव के ग्रामीण दोबारा केलपानी में डेरा डाले हुए थे, शनिवार को आदिवासियों ने मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत आने वाले पुराने गांव भी जाने का फैसला किया था.

इसी फैसले के तहत वे शनिवार से केलपानी में रुके हुए थे. लेकिन सोमवार को विधायक बच्चू कडू की मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस से हुई चर्चा के बाद आदिवासियों ने अपने पुनर्वसित गांवों की ओर लौटना आरंभ कर दिया था. इस संदर्भ में अकोला के जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय ने बताया कि अकोट तहसील में उपलब्ध 200 एकड़ ई-क्लास जमीन की शासकीय खानापूर्ति को प्राथमिकता देते हुए आगामी पखवाड़े के भीतर आदिवासियों को उपलब्ध जमीन के अनुपात में भूमि का आवंटन आरंभ कर दिया जाएगा, जिन लोगों को अकोट में खेती के लिए जगह नहीं मिलेगी उन्हें अमरावती जिले के धारणी एवं चिखलदरा परिसर में उपलब्ध ई-क्लास जमीन दी जाएगी.

ज्ञात हो कि शनिवार से मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत आने वाले गांवों के पुनर्वसित आदिवासी खेती के लिए जमीन न मिलने से क्षुब्ध होकर अपने मूल गांवों की ओर लौटने लगे थे, जिसे देख अकोट के उपविभागीय राजस्व अधिकारी उदय राजपूत, उपवन संरक्षक गुरुप्रसाद आदि ने आदिवासियों से बातचीत कर उनसे वापस जाने की विनती की थी. लेकिन आदिवासी ठोस आश्वासन चाहते थे.

मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत आने वाले आमोना, बालखेड़ा, सोमठाणा बु., सोमठाणा खु., गुल्लर घाट, नागरतास तथा केलपानी इन 8 गांवों के ग्रामीणों ने खेती के लिए जमीन, पेट भरने के लिए काम एवं बुनियादी सुविधाएं तथा स्वास्थ्य व चिकित्सा सुविधा के साथ श्मशान भूमि की व्यवस्था करने की मांग का मुद्दा उठाते हुए विगत 9 सितंबर को अपने परिजनों के साथ मेलघाट की ओर प्रस्थान किया था.

उस दौरान विभागीय आयुक्त पीयूष सिंग, मुख्य उपवन संरक्षक श्रीनिवास रेड्डी, अकोला के जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, अमरावती के जिलाधिकारी अभिजीत बांगर ने मेलघाट में ग्रामीणों से उनके गांव वापस जाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया था. लेकिन व्यवस्था में हो रही देरी के साथ आदिवासियों को खेती करने के लिए जमीन दिए जाने की मांग वे कर रहे थे. इसी मुद्दे को लेकर विगत दो दिनों से सैकड़ों आदिवासी पोपटखेड़ समीप के केलपानी में डेरा डाले हुए थे. नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन के लिए नागपुर में उपस्थित मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस, अचलपुर के विधायक बच्चू कडू, तुषार फुंडकर, शंभु माल्ठाणे के बीच सकारात्मक वार्ता हुई जिसमें आदिवासियों की रोजगार की समस्या तथा बुनियादी आवश्यकताओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया कि अकोट तहसील में उपलब्ध 200 एकड़ ई-क्लास जमीन के अलावा धारणी तथा चिखलदरा परिसर में बड़े पैमाने पर उपलब्ध ई-क्लास जमीन को पुनर्वसित आदिवासियों को खेती के लिए एवं रहने के लिए दी जाए, जिसके लिए शासन की ओर से आवश्यक खानापूर्ति करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने देते हुए प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की हिदायत दी, ताकि आदिवासियों को शीघ्र जमीन की उपलब्धता के अनुसार खेती के लिए उन्हें जमीन दी जा सके. इस संदर्भ में विधायक बच्चू कडू ने बताया कि आज की चर्चा सफल रही है. मुख्यमंत्री महोदय ने आदिवासियों की परेशानी को समझते हुए उपलब्ध जमीनों में से अधिकतम 2 हजार हेक्टेयर तक की जमीन समान रूप से आदिवासी परिवारों में बांटने के लिए अंतिम फैसला लिया है.

इस संदर्भ में मिले आश्वासन की जानकारी जैसे ही केलपानी में डेरा डाल बैठे आदिवासियों को हुई तथा विधायक बच्चू कडू ने फोन कर उन्हें वापस जाने की हिदायत देने के बाद आंदोलन कर रहे आदिवासी अपने पुनर्वसित गांवों की ओर लौटने लगे थे.

15 दिन में आरंभ होगी प्रक्रिया

अकोला के कलेक्टर आस्तिक कुमार पाण्डेय ने बैठक के संदर्भ में बताया कि सरकार ने सकारात्मक रवैया अपनाते हुए आदिवासियों को उपलब्ध जमीन देने का निर्णय लिया है. इस संदर्भ में शासकीय आदेश मिलते ही संबंधित आदिवासी परिवार प्रमुखों की बैठक लेकर जमीनों के आवंटन के संदर्भ में फैसला लिया जाएगा. अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए शासन स्तर पर व स्थानीय जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक कार्रवाई जारी है.